MEDIA/LKO/0019

लखनऊ | 25 नवंबर 2014 मंगलवार बिज़नेस स्टैंडर्ड p-2

उत्तर प्रदेश में 20 चीनी मिलों ने शुरू की पेराई

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 24 नवंबर

उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि राज्य की ज्यादातर चीनी मिलें इस महीने के अंत तक पेराई शुरू कर देंगी। फिलहाल कम से कम 20 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है।

राज्य में 119 चीनी मिलें हैं जिनमें 95 निजी और 23 सहकारी और एक उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना निगम लिमिटेड (यूपीएसएससीएल) हैं। इनमें से काम करने वाली 12 और 8 मिलें क्रमश: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि पेराई निर्धारित समय के बाद शुरू हुई है लेकिन राज्य सरकार ने दावा किया है कि पिछले साल के मुकाबले पेराई की शुरुआत खासी अच्छी रही है।

पिछले महीने सरकार सरकार ने मिलों को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्रमश: 10 नवंबर और 15 नवंबर से पेराई शुरू करने का आदेश दिया था। हालांकि पहली निजी और सहकारी मिलें क्रमश: 10 और 14 नवंबर को ही पेराई शुरू कर पाईं। 2013-14 सत्र में इन्होंने पेराई क्रमश: 27 नवंबर और 18 को शुरू किया था।

इस बीच, निजी चीनी मिलों पर पिछले सत्र का 1,288 करोड़ रुपये बकाया हैं। इस तरह, मिलों ने किसानों को 2013-14 के लिए कुल 19,388 करोड़ रुपये में 18,100 करोड़ रुपये दिए थे। यानी मिलों ने 93 प्रतिशत भुगतान कर दिया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भारी-भरकम बकाया रकम को लेकर राज्य सरकार और निजी चीनी मिलों को फटकार लगाई जा चुकी है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में गन्ना किसानों को अब तक 48,499 करोड़ रुपये भुगतान हो चुका है। इनमें मायावती शासनकाल के 5,700 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने मार्च 2012 में मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी।

पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के चीनी क्षेत्र को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। राज्य में औसत गन्ना उत्पादन और चीनी रिकवरी दर क्रमश: 62 टन प्रति हेक्टेयर और 9.27 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 70 टन प्रति हेक्टेयर और 10.25 प्रतिशत है। इससे किसानों और मिलों दोनों को कम फायदा मिलता है। राज्य सरकार अब गन्ना उत्पादन और इसमें रस की मात्रा बढ़ाने के लिए गन्ने की बेहतर किस्म लगाने की कोशिश कर रही है।